



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2018/पौष 11, 1939

No. 02]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2018/PAUSHA 11, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

मामला सं. एनएसआर- 03/2017

(न्यू शिपर समीक्षा)

विषय : बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" अर्थात् - जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टिपल फोल्डेड/केबल्ड और एकल) हेसियन फेब्रिक और जूट की बोरियों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के मामले में मै. जनता जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक) के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत

फा. सं. 7/10/2017-डीजीएडी.—बंगलादेश में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक मै. जनता जूट मिल्स लि.(उत्पादक) (जिसे आगे "जनता" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के पाटित आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले में उनके लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण को अनुरोध किया गया है। उक्त शुल्क मूल पाटनरोधी मामले में 20 अक्टूबर 2016 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 द्वारा और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 3 अप्रैल, 2017 द्वारा लगाये गए थे।

शामिल उत्पादक/निर्यातक

1. वर्तमान जाँच अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के अनुसार मै. जनता जूट मिल्स लि. (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा जूट उत्पादों विशेष रूप से जूट की बोरियों के प्रस्तावित निर्यातों से संबंधित है।

नये उत्पादक/निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरुआत

2. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निम्नानुसार उल्लेख है :

22. ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनकी मूल रूप से जाँच नहीं की गई थी -(1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जाँच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जाँच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।"

इन पाटनरोधी नियमों में प्राधिकारी के लिए जाँच के अधीन निर्यातक देश में किसी निर्यातक या उत्पाद के लिए पाटन का अलग मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा की शुरुआत करना अपेक्षित है जिसने पूर्ववर्ती जाँच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और यह कि याचिकाकर्ता निर्यातक देश में ऐसे किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिनके संबंधित उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगता है।

मै. जनता जूट मिल्स लि. (उत्पादक-सह-निर्यातक) ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी, प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होते हुए कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन यथा विहित शर्तें पूरी होती हैं, एतद्वारा मूल पाटनरोधी मामले में 20 अक्टूबर 2016 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 द्वारा और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 3 अप्रैल, 2017 द्वारा प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादों के पाटित आयातों पर लगाये गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में उनके अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं।

3. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 द्वारा और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को ध्यान में रखते हुए मै. जनता जूट मिल्स लि. द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों के संबंध में इस समीक्षा के पूरे होने तक अनंतिम आकलन करने की सिफारिश करते हैं।

जाँच अवधि

4. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2018 तक की है।

सूचना प्रस्तुत करना :

5. ज्ञात हितबद्ध पक्षों को विहित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

6. इस समीक्षा से संबंधित समस्त सूचना उक्त पैरा 4 में यथा उल्लिखित जाँच/समीक्षा अवधि के पूरा होने की तारीख से 40 दिनों से पहले-पहले उक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त

सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में के आधार पर अपने जाँच "उपलब्ध तथ्यों" परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

7. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

8. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

9. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

10. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

11. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

12. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

13. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

14. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2018

Case No. NSR- 03/2017

(New Shipper Review)

Subject : Initiation of New Shipper Review under Rule 22 of the Anti-Dumping Rules for determination of individual dumping margin for M/s Janata Jute Mills Limited (Producer) in the case of Anti-dumping duty imposed on "Jute Products" viz – Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Sacking Bags originating in or exported from Bangladesh and Nepal.

F. No. 7/10/2017-DGAD.—M/s. Janata Jute Mills Limited (Producer) (hereinafter referred to as "Janata"), a producer of the subject goods from Bangladesh has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Act) as amended from time to time and Customs

Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) requesting for determination of their individual dumping margin in the matter of anti-dumping duties levied on imports of “Jute Products” originating in or exported from Bangladesh and Nepal. The said duties were imposed vide Final Findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016 and Customs Notification No. 01/2017 – Cus (ADD) dated 5th January, 2017 and Customs Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017 in the original Anti-Dumping case.

PRODUCER/EXPORTER INVOLVED

1. The present investigation relates to proposed exports of Jute Products by M/s Janata Jute Mills Limited (Producer and Exporter) specifically Jute Sacking Bags in terms of the application filed before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules.

INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW PRODUCER / EXPORTER

Rule 22 of Anti-Dumping Rules states as under:

22. Margin of Dumping, for exporters not originally investigated - (1) “If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the antidumping duties on the product.”

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”

These AD Rules thereby require the Authority to initiate review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier investigations and that the petitioner/s is/are not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the anti-dumping duty.

M/s. Janata Jute Mills Limited (producer cum exporter) have provided necessary information as required under Rule 22 of AD Rules. The Authority, having been *prima facie* satisfied that the conditions as prescribed under Rule 22 of AD Rules are met with, hereby decides to initiate a New Shipper Review investigation for determination of their individual dumping margin in relation to the anti-dumping duties levied on dumped imports of Jute Products originating in or exported from Bangladesh and Nepal in pursuance of the recommendations made by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016 and Customs Notification No. 01/2017 – Cus (ADD) dated 5th January, 2017 and Customs Notification No. 11/2017 – Cus (ADD) dated 3rd April, 2017 in the original Anti-Dumping case.

2. The Authority recommends provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Janata Jute Mills Limited till this review is completed, in accordance with Rule 22 of the AD Rules and having regard to Customs Notification No. 01/2017 – Cus (ADD) dated 5th January, 2017 and Customs Notification No. 11/2017 – Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.

PERIOD OF INVESTIGATION:

3. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st January, 2017 to 30th June, 2018.

SUBMISSION OF INFORMATION:

4. The Known interested parties are being informed separately to enable them to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated

Authority, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi -110001. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation to the above Authority in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT:

5. All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty days from the date of completion of the Period of investigation/Review as stated in para 4 above. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available before the Authority in accordance with the AD Rules.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS.

6. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
7. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non- confidential version must be submitted.
8. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
9. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Designated Authority.
10. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
11. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Designated Authority. The Designated Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE:

12. In terms of Rule 6(7) of Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
13. In case where as interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority